संशोधित अनुमान, 2003-2004

वर्ष 2003-2004 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान में बजट अनुमानों की तुलना में 11,143 करोड़ रुपए की निवल कमी दर्शायी गई है जिसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के प्रति देयताओं के पुनर्भुगतान के मद में 46,602 करोड़ रुपे का व्यय शामिल नहीं है, जिसे राज्य ऋण अदला-बदली स्कीम के अंतर्गत प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित किया गया है। जहां आयोजना-भिन्न व्यय जिसमें एनएसएसएफ के प्रति देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है, में 11,676 करोड़ रुपए की कमी हुई है वहीं आयोजना व्यय में 533 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख मदों में घट-बढ़ हुई है उन्हें नीचे दर्शाया गया है :–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2003-04	संशोधित 2003-04	घट-बढ़
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय	123223	120475	(-) 2748
2. पूर्व-भुगतान प्रीमियम	...	4080	(+) 4080
3. रक्षा	65300	60300	(-) 5000
4. खाद्य सब्सिडी	27800	25200	(-) 2600
5. उर्वरकों पर सब्सिडी	12720	11797	(-) 923
6. पेट्रोलियम सब्सिडी	8116	6573	(-) 1543
7. उद्योग और खनिज	473	3001	(+) 2528
8. राज्यों को अनुदान/ऋण	18035	15017	(-) 3018
9. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	62154	59702	(-) 2452
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	**317821**	**306145**	(-) **11676**
आयोजना			
1. केन्द्रीय आयोजना	72152	72847	(+) 695
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता	48822	48660	(-) 162
जोड़ (आयोजना) व्यय	**120974**	**121507**	**(+) 533**

आयोजना-भिन्न

1. ब्याज दरों और सरकारी प्रतिभूतियों के पुनःनिर्गम पर अर्जित प्रीमियम में कमी के कारण।
2. उच्च लागत वाले विदेशी ऋण समाप्त करने के लिए पूर्व-भुगतान प्रीमियम और घरेलू ऋण की वापसी-खरीद।
3. मुख्यतया कम पूंजी व्यय के कारण।
4. मुख्यतया खाद्य भंडारों की वहन लागत में कमी के कारण
5. यूरिया के आयात में कमी और विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के अंतर्गत कम आवश्यकता के कारण है।
6. कमी एक निश्चित समयावधि में पेट्रोलियम सब्सिडी को क्रमशः समाप्त करने के निर्णय के अनुरूप है।
7. वृद्धि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को उनके पुनर्गठन मे सहायता के लिए अनुदानों के कारण है।
8. कमी अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय निकायों को अनुदानों के अंतर्गत निधियों के अल्प उपयोग, उन्नयन/विशेष समस्या अनुदान आदि और वैट के लागू करने पर राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति के प्रावधान के उपयोग न होने के कराण है।

आयोजना

1. आयोजना व्यय में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास, सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और रेलवे के लिए बजटीय सहायता के कारण है।
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अधीन वृद्धि और सामान्य केन्द्रीय सहायता में कमी, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम और शहरी आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के अभिक्रम और विकास तथा सुधार सुविधा के निवल प्रभाव से कमी हुई है।